भारत में 2018 से 2022 तक 8,756 मृत्यु report हुई हैं due to collapse of structures। इन सभी का निर्माण आम आदमी के मेहनत के टैक्स से होता है और ये घटनाएँ सरकारी कार्यों की गुणवत्ता पर प्रश्न खड़ा करती हैं। आम जनता अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षित सुविधाएं प्रदान करें। इन स्थलों की क्वालिटी और सेफ्टी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके और जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।

महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि सभी सार्वजनिक परिवहन स्थलों का नियमित रूप से ऑडिट किया जाए। इस ऑडिट में विशेषज्ञों की टीम द्वारा विस्तृत निरीक्षण, माप और मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, ताकि किसी भी संभावित जोखिम का समय पर पता लगाया जा सके और उसे ठीक किया जा सके। इसके अलावा, ऑडिट के आधार पर आवश्यक रिपेयर और सुधार कार्य तुरन्त किए जाएं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shri Raghav Chadha: Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Muzibulla Khan (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Sanjeev Arora (Punjab), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla, Shri Haris Beeran (Kerala) and Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala). देशभर में जितने स्ट्रक्चर हैं, उन सबका ऑडिट कराया जाए।

श्री राघव चड्ढा: सर, जहां पर public transport sites हैं। अभी आपने दिल्ली में देखा, जो वारदात हुई। वह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इन सबका रेग्युलर स्ट्रक्चरल ऑडिट एक नियमित तरीके से होना चाहिए, यह मांग की है।

Demand for central assistance for the revival of agricultural sector in the state of Kerala

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Sir, thank you for allowing my Special Mention. The State of Kerala is passing through a tough phase consequent to the heavy landslides at Wayanad that has devastated the lives of people. The extreme weather conditions are constantly creating havoc in the State. Agriculture is one of the major sectors which bears the brunt of climate change and the subsequent weather extremities. The severe drought in Kerala during the summer of 2024 is estimated to have caused direct crop damage to 23,700 hectares across the State and a loss of Rs. 260 crore. Indirectly, there is a loss of production in 23,000 hectares and the loss is estimated at Rs. 250 crore. More than half a lakh farmers have been

affected by the drought.Farmers belonging to the major agricultural districts of Idukki, Wayanad, Palakkad and Thrissur have suffered significant losses. The harsh drought has resulted in partial or complete losses of both food and cash crops. It is learnt that Government of Kerala has approached the Central Government for additional funds to address the situation and support the affected farmers.

In this context, I appeal to the Central Government to grant a special financial package for the revival of agricultural sector in the state. It is requested to issue directions to Banks to write off the agricultural loans of the farmers whose crops have been destroyed. I further urge the Government to provide special financial assistance to the people of Wayanad for compensating the losses in agriculture and livestock. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by Shrimati Jebi Mather Hisham: Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shri Anil Kumar Yadav Mandali (Telangana), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala) and Shri Muzibulla Khan (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala).

Dr. Fauzia Khan is not present. Now, Dr. Sikander Kumar.

Concern over quality of food and hygiene provided by Railways during travel

डा. सिकंदर कुमार (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान भारतीय रेलवे, जिसको देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज भी ट्रेन से सफर करना हर भारतीय के जीवन का हिस्सा है। रेलवे द्वारा सफर के दौरान बहुत से ट्रेनों मे खाने की सुविधा भी दी जाती है। रेलवे द्वारा सफर के दौरान यात्रियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता और साफ-सफाई से लोगों को बड़ी निराशा होती है।

मेरा माननीय रेलवे मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि साफ-सुथरे और पौष्टिक खाने के लिए उचित नीति तथा ट्रेनों एवं स्टेशनों पर अनाधिकृत विक्रेताओं की मौजूदगी रोकने के लिए और रेलवे यात्रियों की शिकायतों का त्वरित निवारण के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाए। इस सम्बन्ध में भारत के रेलवे स्टेशनों के आस पास जो भी गांवों की स्वयं सेवी महिलाओं की संस्था या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क करके, रेलवे मे पौष्टिक घर का खाना उपलब्ध कराने की योजनाओं की भी समीक्षा की जानी चाहिए, जिससे स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और यात्रिओं को पौष्टिक खाना भी मिल सकेगा।

मैं रेलवे मंत्रालय और सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं, धन्यवाद।